

Regarding request for inclusion of tribal dominated villages of Jalgaon constituency under the Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान जलगांव लोकसभा क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित विकासात्मक आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरे जलगांव लोकसभा क्षेत्र में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 34 ऐसे ग्राम हैं, जहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से भी अधिक है। अमलनेर, भडगांव, चालीसगांव, धरणगांव, एरंडोल, पारोला, जलगांव एवं पाचोरा-इन सभी तहसीलों में जनजातीय बहुल आबादी रहने के बावजूद इन्हें अभी तक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान" में शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, यह अभियान हमारे आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पेयजल, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे मूलभूत अधिकारों से संपन्न करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। यदि इन 34 ग्रामों को इससे वंचित रखा गया, तो विकास की एक गंभीर असमानता उत्पन्न होगी, जो इन क्षेत्रों की प्रगति को बाधित करेगी।

अतः मैं केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करती हूँ कि जलगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी 34 जनजातीय बहुल ग्रामों को तत्काल "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान" में सम्मिलित किया जाए तथा इनके लिए विशेष विकास पैकेज, आधारभूत सुविधाएँ और प्रगति की निगरानी हेतु एक सशक्त तंत्र स्थापित किया जाए। यह कदम हमारे आदिवासी भाइयों-बहनों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में अत्यंत निर्णायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।